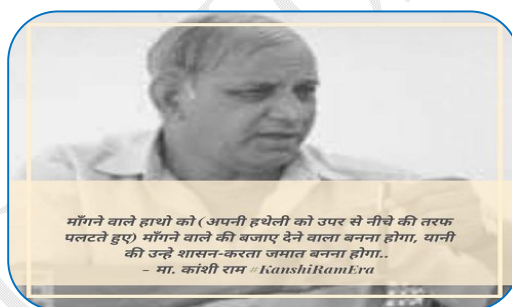




भारत में आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तन करने में मा. कांशीराम का ऐतिहासिक योगदान

डॉ. पी. एस. चंगोले
वाणिज्य विभाग प्रमुख, धनवटे नेशनल कॉलेज, नागपुर.

मा. कांशीरामने अपने संघटन को अधिक मजबूत बनाया. कार्यकर्ताओंका प्रशिक्षण करवाया. आंदोलन का उद्देश समझाया. कार्य करते समय जोश के साथ होश रखनेका पाठ सिखाया. आपस में भाईचारा मजबूत करनेपर ध्यान केंद्रित किया. लोगोंको जानकार बनानेके लिये डा. बाबासाहब अम्बेडकर के संघर्ष का इतिहास बताया.



‘पूना पैक्ट’ के ‘धिव्कार’ कार्यक्रमों का आयोजन : जिस गांधी

आम्बेडकर समझौता बनाम ‘पूना पैक्ट’ की संक्षिप्त चर्चा हम शुरुआत में कर चुके हैं, उसे 1982 में पचास वर्ष पूरे होने जा रहे थे। 1932 के पश्चात स्वयं डा. बाबा साहब आम्बेडकर ने कई मौकों पर इस समझौते से दलित शोषित समाज की हुई हानियों को उजागर करके, इसकी तीव्र निंदा की थी। उसी ‘पूना पैक्ट’ के ‘धिव्कार’ कार्यक्रम

का कांशीराम ने ऐलान किया। 24 सितम्बर, 1982 को पूना से शुरुआत करके 24 अक्टूबर, 1982 को जालंधर में इसका समापन किया। पूना, अहमदनगर, औरंगाबाद, अंबेजोगाई, नांदेड, नागपुर, अकोला, अमरावती, यवतमाल, चंद्रपुर, कोरबा, रायपुर, जबलपुर, इंदौर, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, चउमा, छारा, कोसीकलान, भरतपुर, फरीदाबाद, गाजियाबाद, दिल्ली, भोपाल, झांसी और जालंधर आदि शहरों में ‘पूना पैक्ट धिव्कार परिषदों’ का सफल आयोजन किया गया, इस विराट आयोजन से दलित शोषित समाज में अपने खुद के बदौलत अपने पैरों पर खड़े होने की आकांक्षा जाग उठी। इन परिषदों ने उन बुर्जुआ आम्बेडकरवादियों की धज्जियाँ उड़ा दीं, जो गाँधी के आगे घुटने टेक चुके थे।

2 से 8 दिसम्बर, 1982 तक कांशीराम ने जापान के ओसाका शहर में ‘विषमता के विरुद्ध जातिगत परिषद’ में संसार भर के मानव अधिकार संगठनों के प्रतिनिधियों को भारतीय दलित-शोषितों की समस्याओं से अवगत कराया। इस कार्यक्रम का आयोजन जापान के बुराका लिबरेशन लीग ने किया था।

‘लिमिटेड पोलिटिकल अक्शन प्रोग्राम’ के तहत डी.एस.फोर के बैनर पर दिल्ली का चुनाव भी लड़ा गया, जिस से कार्यकर्ताओं में अनुभव और आत्मविश्वास की वृद्धि हुई।

‘पूना पैक्ट धिव्कार परिषदों’ के पश्चात् कांशीराम जी ने डी.एस.फोर को चार सूत्रीय कार्यक्रम दिया। पहला तात्कालिक (सामाजिक कार्यक्रम) दूसरा अल्पकालीन (सीमित राजनैतिक कार्यक्रम) तिसरा दीर्घकालीन (संपूर्ण राजनैतिक कार्यक्रम) और चौथा स्थायी (सांस्कृतिक बदलाव एवं नियंत्रण) था।

‘डी.एस.फोर का प्रचार दो पैर और दो पहियों का कमाल’ अभियान में सुकी सलाह नहीं देता हमेशा गिली सलाह देता हूँ – कांशीराम ने 3200 कि. मि. सायकल चलाई

डी.एस.फोर का सामाजिक कार्रवाई के अंतर्गत 'डी. एस. फोर का प्रचार दो पैर और दो पहियों का कमाल' अभियान 15 मार्च 1983 से शुरू हुआ। भारत के सभी शहरों, गावों और दूरदराज के देहातों में लगभग 40 दिनों तक 'साईकिल मार्च' चलता रहा। 3200 किलोमीटर की इस लम्बी यात्रा का नेतृत्व स्वयं काशीराम ने किया। इस 'साईकिल मार्च' से आम्बेडकरवादी मिशन का प्रचार प्रसार जिस तेजी से हुआ, डी.एस.फोर का नाम भी भारत के कोने कोने में गूँज उठा। 14 अप्रैल 1983 को दिल्ली में इसका समापन हुआ।

शराब बंदी आंदोलन : इसके तुरंत बाद उत्तरप्रदेश में डी.एस. फोर के माध्यम से राज्यव्यापी शराब बंदी आंदोलन चलाया गया, इसमें यू.पी. की महिलाओं ने बढचढ कर हिस्सा लिया। उत्तरप्रदेश तो जैसे डी.एस. फोर का मायका बन बैठा।

'समता और आत्मसम्मान' का सामाजिक आंदोलन : 6 दिसम्बर, 1983 से कन्याकुमारी, कारगिल, कोहिमा और पुरी में 'समता और आत्मसम्मान' का सामाजिक आंदोलन चलाया गया, जिसका समापन 15 मार्च, 1984 को दिल्ली के बोट क्लब मैदान पर किया गया। यह महाभियान भी अत्यंत सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ।

बामसेफ द्वारा चलाया गया 'पे बॅक टू द सोसायटी' आंदोलन और उसका प्रबोधन कॅम्प, कडर कॅम्प, तथा बुद्धि श्रम और अर्थ स्रोत के निरंतर प्रवाह से गैर-राजनैतिक जड़ों को मजबूती प्राप्त हो रही थी और साथ ही साथ डी.एस. फोर द्वारा चलाये गये जनजागरण अभियान और आंदोलनात्मक गतिविधियों तथा चुनावी राजनीति में प्रभावी उपस्थिति यह सब कुछ मिला कर इस देश के पचासी प्रतिशत दलित-शोषित समाज को बाबासाहब आम्बेडकर के कथन,

'जाओ और अपने घर की दीवारों पर लिख दो कि, हमें इस देश की शासनकर्ता जमात बनना है'

की याद दिलाता रहा, दलित-शोषित समाज की आँखें अब खुलने लगी थीं। वे इस सच्चाई को समझने लगे थे, जो बाबासाहब ने कहा था कि,

'राजनैतिक सत्ता वह गुरुकिल्ली है जिसे हासिल करने से कोई भी ताला खोला जा सकता है।'

परंतु इस सच्चाई को हकीकत में बदलने के लिये किसी ऐसे राजनैतिक दल की आवश्यकता थी जो वास्तव में उनका अपना हो।

काशीराम इस वास्तविकता को समझते थे। लड़ाई का स्वरूप और समय के अनुसार हथियारों का बदलना भी वे जानते थे। डी.एस. फोर की सीमित राजनैतिक कार्रवाई से प्राप्त अनुकूल परिणामों से वे प्रसन्न थे। दलित-शोषित समाज भी अब उन्हें सिर्फ 'साहब' या 'मान्यवर' संबोधित करने लगा था और काशीराम जिसे अब 'बहुजन समाज' कहने लगे थे।

बहुजन समाज पार्टी की स्थापना : भारतवर्ष का पचासी फीसदी दलित शोषित-उपेक्षित समाज अपने किसी राजनैतिक दल को स्वीकार करने के लिये तैयार था। इन संकेतों को समझ कर 14 अप्रैल 1984 को, डा. बाबासाहब आम्बेडकर के जन्मदिवस के अवसर पर, दिल्ली के बोट क्लब मैदान में, मान्यवर काशीराम ने 'बहुजन समाज पार्टी' की स्थापना का ऐलान कर दिया।

इसके साथ ही, 30 मार्च को नागपुर से 'बहुजन टाईम्स' नामक मराठी दैनिक अखबार और 14 अप्रैल, 84 को दिल्ली से एक अंग्रेजी और एक हिन्दी दैनिक अखबार 'बहुजन टाईम्स' प्रकाशित किये गये।

बहुजन समाज पार्टी का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली के लालकिला मैदान पर 22 से 24 जून, 1984 तक आयोजित किया गया। सम्पूर्ण सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का नारा इसी क्षण से बुलंद किया गया।

ओबीसी की समस्या – राष्ट्रीय समस्या
“मंडल आयोग लागू करो बरना कुर्सी खाली करो”
वोट से लेंगे सीएम – पीएम, मंडल से लेंगे एसपी – डीएम

बहुजन समाज पार्टी ने “मंडल आयोग लागू करो बरना कुर्सी खाली करो” का नारा देकर, सारे भारत को झकझोर डाला। इस आंदोलन के तहत 1 अगस्त, 1984 से 14 अगस्त 1984 तक, दिल्ली के बोट क्लब मैदान पर, जेल भरो आंदोलन किया गया, जिस में हजारों बसपा कार्यकर्ताओं ने जिन में महिलायें भी थीं, गिरफ्तारी दी। ऐसे ही अनेक प्रदर्शन और आंदोलन देश के अन्य राज्य और जिला मुख्यालयों में किये गये। ‘मंडल आयोग’ के लिये यह सबसे पहला आंदोलन था।

इसके तुरंत बाद 15 अगस्त 1984 से देश के पांच कोनों से ‘अखिल भारतीय राजनैतिक कारवाई गुलामी के विरुद्ध संघर्ष’ आंदोलन चलाया गया, जिसका उद्देश्य बहुजन समाज, विशेषतः अन्य पिछड़े वर्गों को, समझाना था कि आजादी के 37 वर्षों के बाद भी वे गुलाम क्यों हैं ?

इसी वर्ष 13 नवम्बर, 1984 को लोकसभा चुनाव घोषित हुए। बसपा को स्थापित हुये सिर्फ सात माह हुये थे, फिर भी, बसपा ने नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में अपने उम्मीदवार खड़े किये। इस चुनाव में बसपा को दस लाख से भी अधिक वोट प्राप्त हुये, जिसमें से अकेले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में बसपा ने शिरकत की और केवल दो माह के भीतर ही उत्तर प्रदेश में बसपा के वोटों में 3 लाख की बढ़ोत्तरी हुई।

18 अगस्त, 1984 से 31 दिसम्बर, 1984 तक बहुजन समाज पार्टी ने ‘आरक्षण हिस्सेदारी का सवाल’ इस विषय पर देश भर में पांच विशाल सेमिनार और पांच सौ संगोष्ठियाँ आयोजित कीं। यह आंदोलन मंडल आयोग लागू करवाने के लिये बहुजन समाज में जागृति पैदा करने के लिये किया गया।

5 अक्टूबर 1986 को नागपुर में मंडल आयोग एवं आरक्षण परिषद् आयोजित की गयी।

मार्च, 1987 में हरिद्वार में हुये सांसदीय उपचुनाव में बसपा काफी मजबूती से लड़ी थी। इस चुनाव से कांशीराम की शिष्या मायावती को सारा भारत पहचानने लगा। मायावती को 1,35,311 वोट मिले थे। वे दूसरे नंबर पर थीं जब कि जनता दल के दिग्गज नेता श्री रामविलास पासवान मात्र 35,225 वोट ले कर चौथे स्थान पर थे। उनकी जमानत जब्त हो चुकी थी, जबकि कांग्रेस के विजयी उम्मीदवार को मायावती से मात्र चौदह हजार वोट अधिक प्राप्त हुये थे।

‘भाईचारा बनाओ’ अभियान : 15 अगस्त, 1987 से 15 अगस्त 1988 तक कांशीराम ने देशभर में अस्पृश्यता, अमानवीयता, अन्याय, असुरक्षितता और असमानता, इन पांच सूत्रों के विरोध में, आंदोलन एवं वोट क्लब दिल्ली में धरना आयोजित किया, जिसके तहत देशभर में ‘भाईचारा बनाओ’ अभियान चलाया गया।

भारतीय शरणार्थी आंदोलन, भारतीय किसान और मजदूर आंदोलन, भारतीय दस्तकार आंदोलन (15/08/1988) : संपूर्ण भारत में यह आंदोलन 15 अगस्त 1988 से सुरु किया गया था।

समाज परिवर्तन का पांच सूत्री कार्यक्रम (17/09/1988 – 17/09/1989) : पेरियार के जन्मदिन के मौके पर 17 सितम्बर 1988 से भारत के पांच प्रमुख शहरों से – कन्याकुमारी (तामिलनाडू) से दिल्ली, कोहिमा (नागालैंड) से दिल्ली, कारगिल (काश्मिर) से दिल्ली, पुरी (ओरिसा) से दिल्ली, पोरबंदर (गुजरात) से दिल्ली सायकल मार्च आयोजित किया गया। उस आंदोलन के पांच सूत्र थे – 1. आत्मसम्मान के लिए संघर्ष 2. स्वतंत्रता के लिए संघर्ष 3. समानता के लिए संघर्ष 4. जातिनिर्मूलन तथा भाइचारे के लिए संघर्ष 5. अस्पृश्यता, अन्याय, अत्याचार तथा आतंकवाद के विरोध में संघर्ष।

1989 के चुनाव में बसपा उत्तरप्रदेश में ‘बैलेन्सिंग पावर’ के रूप में नजर आयी। प्रदेश में लोकसभा की दो और विधानसभा की 23 सीटों पर कब्जा करके उसने तमाम राजनैतिक पार्टियों को चौंका दिया। इसी वर्ष पंजाब से बसपा ने लोकसभा की भी एक सीट जीती। बसपा को उत्तरप्रदेश और पंजाब में राज्यस्तरीय मान्यता प्राप्त हुई।

6 दिसम्बर, 1990 से 14 अप्रैल 1991 तक मा. कांशीराम ने सुदूर दक्षिण भारत के कन्याकुमार से 'सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति' के आंदोलन की शुरुआत की। यह डा. बाबासाहब आम्बेडकर की जन्मशताब्दी का वर्ष था। भारत के 13 प्रमुख और बड़े राज्यों में शहरों से लेकर गांवों और सुदूर देहातों तक, डा. बाबासाहब आम्बेडकर की विचारधारा का प्रचार प्रसार किया गया। मंडल आयोग लागू करवाने के लिए पिछड़े वर्गों में जागृति लाना भी इस कार्यक्रम में शामिल था। 'सामाजिक परिवर्तन रथ' के साथ करीब 50 हजार किलोमीटर लम्बी यात्रा, तामिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, जम्मू-काश्मीर, चंडीगढ़ आदि राज्यों का दौरा करती हुई 15 मार्च, 1991 को मान्यवर कांशीराम के जन्मदिवस के अवसर पर दिल्ली के वोट क्लब पर विराट सभा में परिवर्तित हुई, जिसमें बहुजन समाज ने लाखों की तादाद में उपस्थिति दर्शायी।

130 दिनों तक यह यात्रा चलती रही और मान्यवर कांशीराम जी प्रतिदिन औसतन 20 सभाओं को संबोधित करते थे। 14 अप्रैल 1991 को इस महायात्रा का समापन डॉ. बाबासाहब आम्बेडकर की जन्मभूमि महु (मध्यप्रदेश) में किया गया।

इस यात्रा की विशेष घटना यह भी थी कि, जब पंजाब में यह यात्रा पहुंची, तब कांशीराम को कई वर्षों बाद अपने पैतृक गांव जाने का अवसर मिला, उन्होंने अपनी माताजी से भेंट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।

1991 के उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनावों में बसपा को 12 स्थानों पर विजय प्राप्त हुई, और 137 स्थानों पर प्रत्याशी दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे। हरियाणा से 1 प्रत्याशी की विजय हुई।

स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहला मौका था जब दलित शोषित समाज के लोग ना सिर्फ अपना राजनैतिक दल बना कर अपने बलबुते पर चुन कर आये, बल्की मंत्री भी बने। कांशीराम ने वह कर दिखाया, जिसकी कल्पना महात्मा फुले, छत्रपति शाहू, पेरियार रामास्वामी और डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर ने की थी।

‘जाती तोड़ों समाज जोड़ो’ आंदोलन : 6 दिसम्बर, 1993 को डॉ. बाबासाहब आम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर मान्यवर कांशीराम ने अखील भारतीय स्तर पर ‘जाती तोड़ों समाज जोड़ो’ आंदोलन का शंखनाद किया। इस प्रोग्राम के तहत मुम्बई, हैदराबाद, पटना, कलकत्ता और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में विराट रैलियाँ आयोजित की गयीं और स्थानिक स्तर पर भी देश भर में अनेक सभायें सम्पन्न हुई।

बहुजन समाज की सरकार बनी – समाज परिवर्तक महापुरुषोंका सम्मान

भाजपा, जो कि कट्टरपंथी ब्राम्हणवादी का दल है, जब बसपा को समर्थन देने के लिये राजी हुआ, तो यह बात किसी चमत्कार से कम नहीं थी। जिन लोगो ने आज तक दलित – शोषित बहुजन के वोटो को लूट कर अपनी सरकारें बनायी थी। और पिछड़ो को अपने पांवो तले दबाये रखा था, आज वे ही लोग बहुजन समाज की पार्टी को सरकार बनाने में मदद करें ? मगर ऐसा हुआ। और 3 जून, 1995 में देश के सबसे बड़े प्रांत उत्तरप्रदेश में पहली बार दलित – शोषित बहुजन समाज की सरकार बनी। बहन कु. मायावती एक दलित महिला, पहली बार मनुवादियो के गढ़ में मुख्यमंत्री बनी। सपा को छोड़ कांग्रेस सहित अन्य सभी दलों ने बसपा का समर्थन किया। इस प्रकार विरोधियों का समर्थन लेकर सरकार बनाने में मां कांशीराम जी की आलोचना भी हुयी। उन्हें अवसरवादी भी कहा गया, परंतु यह फौलादी पुरुष जरा भी विचलित नहीं हुआ। कांशीराम के दिशा निर्देशन में मायावती बहुजनोद्धारक कार्यों में जुट गयी। सर्वप्रथम 25 – 26 जुलाई 1995 में उन्होंने लखनऊ में विशाल ‘शाहू मेला’ आयोजित किया। अपने समर्थन की कीमत मांगते हुये भाजपा ने मथुरा में विश्व हिंदु परिषद द्वारा यज्ञ आयोजित करवाने की कोशिश की, जिसे मुख्यमंत्री मायावती ने मंजूरी नहीं दी। कानपुर विश्वविद्यालय का ‘श्री छत्रपती शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर’ नामकरण कर दिया। आगरा विश्वविद्यालय को डॉ. बाबासाहब आम्बेडकर, विद्यापीठ’ नामकरण से नवाजा। 26 सितम्बर 1995 को लखनऊ में ‘पेरियार मेला’ आयोजित किया।

दलित – शोषित समाज जहाँ बहुसंख्या में था। ऐसे गांवों में, स्कूल, अस्पताल, जल, सड़क, पक्के रास्ते, बिजली इत्यादी अत्यावश्यक सुविधाओ को उपलब्ध करवाने के लिये हजारों करोड रुपयो की योजना को तेजी से कार्यान्वित किया। इसे ‘आम्बेडकर ग्राम विकास योजना’ कहते हैं।

आम्बेडकर नगर और ऊधमसिंह नगर नामक दो नये जनपदों का निर्माण किया, जिनका घोषणा पत्र 29 सितम्बर 1995 को जारी किया गया।

1.43 लाख शांतिर अपराधियों को गिरफ्तार करके कानून और व्यवस्था को मजबूत कर भ्रष्ट एवं पक्षपाती उच्चाधिकारियों को निलंबित किया।

शासन और प्रशासन पर मायावती की मजबूत पकड़ और बहुजनोद्धारक कार्यशैली से भाजपा का नाराज होना अस्वाभिक नहीं था। परंतु, मायावती जी ने भाजपा के नाराजी की परवाह नहीं की और तेज गति से कार्य करने लगी। 17 अक्टूबर, 1995 को सिर्फ चार माह पूर्ण होते ही भाजपा ने समर्थन वापस ले लिया। परंतु, इन चार महिनो में मायावती ने वह कार्य कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी।

इन चार महिने में दलित – शोषित समाज का आत्मविश्वास जाग गया था। मायावती के कार्यों की सराहना उनके विधायकों ने भी की।

अब काशीराम का कार्य और भी गति से बढ़ गया।

बसपा की गठबंधन सरकार बनते ही मुख्यमंत्री मायावती ने जिस तेजी से कार्य शुरू किया, उसकी मिसाल ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। वे दुसरी बार मुख्यमंत्री बनी थीं। अपने पहले के कार्यकाल में अधूरे रह गये कार्यों को पूरा करने का मौका उन्हें अब प्राप्त हुआ। वे अक्सर कहा करतीं कि, मुझे छः साल का काम सिर्फ 6 महीनों में पूरा करना है।

काशीराम के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री मायावती के शासनकाल के इन छह महीनों में 8 नये जिलों का सृजन हुआ – जिनमें ज्योतिबा फुले नगर, कौशाम्बी, महामाया नगर, छः शाहू महाराज नगर, गौतमबुद्ध नगर, चन्दौली, श्रावस्ती और बलरामपुर का समावेश है।

आम्बेडकर ग्राम विकास योजना के तहत 11,524 गावों में रोड, बिजली, शौचालय, पेयजल, औषधालय, लायब्ररी, स्कूल आदि बनाये गये, जिनका लाभ 12 लाख अनु-जाति और जनजाति के लोगों को मिला। दलित विद्यार्थियों की स्कॉलरशीप बढ़ाई गयी। 100 करोड़ की लागत की महत्वाकांक्षी “डा. बाबासाहब आम्बेडकर उद्यान और स्थल” का भव्य निर्माण, कानपुर में गौतमबुद्ध पार्क, गाजियाबाद में महामाया स्टेडियम, लखनऊ में परिवर्तन चौक का निर्माण, भागीदारी भवन, लाखों भूमिहीनों को जमीन का कब्जा, दलित ऐक्ट का क्रियान्वयन, और कानून और व्यवस्था की बहाली के लिये करीब 1 लाख असामाजिक तत्वों को कैद, किसान, बेघर, वृद्ध और विधवाओं को पेंशन, आदि अनेक उल्लेखनीय कार्य पूरे किये गये।

स्वतंत्र भारत में बहुजन समाज आश्रित क्यों ? – असली आजादी का संघर्ष

इसी काल में, मान्यवर काशीराम ने 15 अगस्त 97 से अखिल भारतीय स्तर पर “असली आजादी का संघर्ष” आंदोलन प्रारंभ किया। इस कार्यक्रम के तहत देश भर में “स्वतंत्र भारत में बहुजन समाज आश्रित क्यों” विषय पर संगोष्ठियां और सेमिनार आयोजित किये गये। देश के सभी राज्यों में ‘जीप मार्च’ आयोजित किया गया, जिसका समापन 15 सितम्बर, 1997 को दिल्ली के लाल किला मैदान पर किया गया, दिल्ली की यह रैली ‘एक महाविराट रैली’ थी, जिसमें दस लाख से भी अधिक की संख्या में बहुजन समाज उपस्थित था।

मुख्यमंत्री मायावती का छह माह का कार्यकाल पूरा होते ही, उन्होंने 20 सितम्बर, 97 को अपने पद से इस्तीफा दिया, और 21 सितम्बर, 97 को भाजपा के कल्याणसिंह मुख्यमंत्री बने। समझौते की शर्त का बसपा ने पालन किया। परंतु भाजपा को इससे समाधान नहीं मिला। बसपा विधायकों को खरीद कर अपनी पूर्ण सरकार बनवाने का षडयंत्र भाजपा ने शुरू किया। बहन कु. मायावती के कार्यकाल में दलित-शोषित समाज के सामाजिक और आर्थिक उत्थान की दिशा में हुये कार्यों से भाजपा वैसा भी आतंकित थी। बसपा का जनाधार काफी बढ़ चुका था। भाजपा ने बसपा के प्रभाव को कम करने के लिये मायावती द्वारा चलाये गये अभियान को रोकना शुरू कर दिया। दलित उत्पीड़न कानून पर रोक लगी। दलितों पर अत्याचार का सिलसिला शुरू हो गया। बाबासाहब आम्बेडकर की प्रतिमाओं का अपमान किया गया। बलात्कार और हत्याएं शुरू हो गयीं। और बसपा

विधायकों को आर्थिक प्रलोभन दे कर, बसपा को तोड़ने की कोशिश की गयी। शाहूजी महाराज नगर जिले का नाम फिर से बदलकर चित्रकूट धाम रखा गया।

19 अक्टूबर, 1997 को मायावतीजी ने कल्याणसिंह सरकार को दिया समर्थन वापस ले लिया। कांग्रेस पार्टी के बहुसंख्य विधायकों और बसपा के कुछ बिकाऊ विधायकों को मंत्रीपद की भीख देकर भाजपा ने अपने पक्ष में कर लिया और कल्याणसिंह सरकार बच गयी।

न बिकने वाला समाज बनाने की मुहिम : कांशीराम ने, न बिकने वाला समाज, एक सशक्त, आत्मनिर्भर और अपने बलबूते पर अपने पैरों पर खड़ा होने वाला समाज निर्माण करने के लिये, जातिविहीन समाज व्यवस्था की स्थापना के लिये अपना जीवन दांव पर लगाया था। परंतु यदि इस समाज में बिकने वाला जीव अपनी कीमत मांगने के लिये बाजार में खड़ा होगा, तो उसे कोई मसीहा भी नहीं बचा पायेगा।

25 नवम्बर, 1997 को भारतीय चुनाव आयोग ने बहुजन समाज पार्टी को अधिकृत तौर पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया। कांग्रेस, भाजपा, माकपा के बाद बसपा चौथे नम्बर की नैशनल पार्टी बनी। भारत के 85 प्रतिशत दलित-शोषित बहुजन समाज की अपनी पार्टी है। अपने निर्माण के सिर्फ 13 वर्षों में राष्ट्रीय दर्जा हासिल करने वाली यह एकमात्र पार्टी है।

1997 के उत्तरार्ध में राष्ट्रीय मोर्चा की केंद्र सरकार अपने अंतर्कलहों के चलते धाराशाही हुई। फरवरी, 1998 में फिर से लोकसभा चुनाव हुये।

1996 में उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, पंजाब और हरियाणा में जिन सीटों पर बसपा को कुल मिलाकर, 1 करोड़ 19 लाख 73 हजार वोट मिले थे, 1998 में उन्हीं सीटों पर कुल मिलाकर, 1 करोड़ 49 लाख 4 हजार अधिक वोट मिले, अर्थात् 29 लाख 32 हजार अतिरिक्त वोट इस प्रकार हासिल हुये। यह बसपा के विलक्षण प्रगति का एक उदाहरण था।

संविधान समिक्षा आयोग के विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन (26/01/2000 – 26/01/2001)

एन. डी. ए. सरकारने भारतीय संविधान की समिक्षा करने के लिये संविधान समिक्षा आयोग गठित किया था। संविधान में उसका कोई प्रावधान नहीं है। संविधान समिक्षा करने का उद्देश्य लोगोंको समझाने के लिए कांशीरामने राष्ट्रीय स्तर पर जीप मार्च निकालकर तथा सेमिनार और हजारों संगोष्ठियोंका आयोजन करके लोगोंको जानकार बनाया तथा एन. डी. ए. सरकार को संविधान समिक्षा आयोग की कार्यवाही रोकने के लिये मजबूर किया।

आरक्षण आंदोलन का शताब्दी समारोह (26/07/2002– 26/07/2003) : महात्मा जोतीराव फुले ने आरक्षण का सिद्धांत बताया। राजर्षि शाहू महाराज ने 26 जुलै 2002 को 50 प्रतिशत आरक्षण देने की सुरुवात की तथा सामाजिक तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व का कानूनी मार्ग दिखाया। इस घटना को 26 जुलै 2002 को 100 साल पुरे हुये थे। आरक्षण आंदोलन शताब्दी समारोह का आयोजन करके कांशीरामने संपूर्ण भारत में राजर्षि शाहू के योगदान की जानकारी पहुंचायी।

बहुजन समाज के लोगों ने पिछले कुछ वर्षों से मान्यवर कांशीराम के जन्मदिवस 15 मार्च को 'बहुजन समाज दिवस' के रूप में मनाना शुरू कर दिया है।

मनुवादी पत्रकारीता का यह एक वास्तव रहा है कि जिन दिनों कांशीराम बामसेफ की प्रभावकारिता और संगठन शैली स्वतः स्पष्ट थी लेकिन उसके पीछे की दूरंदेशी को कोई नहीं पकड़ पाया। 6/12/1978 में बामसेफ बना, ठीक तीन साल बाद 6/12/1981 में डीएस-फोर बनी और उसके ठीक तीन साल बाद 14/04/1984 में बसपा बन गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि किसी को इन संगठनों के निर्माण का यह क्रम नियोजित और गहरे उद्देश्यों वाला नहीं लगा। शायद ही किसी प्रमुख बुद्धिजीवी या समाजविज्ञानी ने कांशीराम को गंभीरता से लिया हो। बहुजनों में काम करने वाली वामपंथी शक्तियां उस जमाने में कुछ-कुछ व्यंग्य के साथ ही साइकिल पर घूमते रहने वाले कांशी राम के बारे में चर्चा करती थीं। समाचार पत्रों में भी डीएस-फोर

की साइकिल यात्राएं खबरों के हाशियों पर हो रह गई। पत्रकार और अन्य प्रेक्षक कांशीराम की बढ़ती हुई लोकप्रियता और 'जय भीम' के अभिवादन का नया मर्म नहीं समझ पाए।

काँग्रेस ने उसे राजनीतिक शरारत करार दिया और 'मौसमी पार्टी' कह कर उसकी अल्पजीविता की भविष्यवाणी कर दी।²

बसपा के पास प्रचार का सस्ता मुख्य साधन साइकिल थी

ऊपर से देखने में बसपा और उसके पूर्ववर्ती संगठनों के पास कोई राजनीतिक तामझाम था भी नहीं। बामसेफ और डीएस-फोर के पास दफ्तर के नाम पर लखनऊ के उदयगंज इलाके में एक श्री.कुरील की कोठरी थी। दिल्ली में कांशीराम रैगरपुरा की घनी बस्ती के एक मामूली से कमरे को अपना केंद्र बनाए हुए थे।³ बसपा के पास प्रचार का मुख्य साधन साइकिल थी और कांशी राम को अपने कार्यकर्ताओं को सलाह थी कि बीस किमी तक पैदल चलो और इसके बाद साइकिल का इस्तेमाल करो। ऐसी साधनहीन पार्टी को वे राजनीतिक ताकतें क्यों मुंह लगातीं जो जीपों और कारों के काफिलों के साथ जनता के बीच में जाती थीं। दूसरे, कांशी राम ने रणनीति भी ऐसी ही बनाई थी कि चुपचाप तैयारी करो और चुनाव के समय उभर कर खड़े हो जाओ।⁴

पासवान को अपनी ही बिरादरी के लोगों के बीच 'ठाकुर की ठप्पा' कहा जाता है। जब ठाकुर चाहते हैं कि पासवान को चुना जाए तो वे अनुसूचित जातियों को वोट नहीं डालने देते और पासवान के पक्ष में 5-6 लाख वोटों पर ठप्पा मार देते हैं। जब वे पासवान को जीतने नहीं देना चाहते तो पासवान को 34,000 वोट ही मिलते हैं।⁹

हरिद्वार में मायावती ने पासवान को ध्वस्त कर दिया। बसपा को 1,35,399 वोट मिले। पासवान को केवल 34,225 वोट नसीब हुए। जीत काँग्रेस उम्मीदवार की हुई लेकिन केवल 14-15 हजार वोटों से। लोकदल और भाजपा उम्मीदवारों का तो पता ही नहीं चला।¹⁰

राजनीति में बसपा को पूरी तरह से स्थापित कर देने के लिए कांशी राम ने दो दांव और मारे। पंजाब विधानसभा चुनाव, बिजनौर और हरिद्वार के उपचुनावों से उन्होंने बहुजन वोटों पर अपनी पकड़ के तथ्य उभारा था लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बसपा द्वारा डाले जा सकने वाले दबाव का नजारा दिखना भी जरूरी था— साथ ही कांशी राम को ऊंचे स्तर पर राजनीतिक जोड़-तोड़ में अपनी कुशलत भी साबित करनी थी। यह मौका उन्हें 1988 में मिला। बोफोर्स मसले पर काँग्रेस छोड़ कर विपक्ष के साथ मिल गए विश्वनाथ प्रताप सिंह इलाहाबाद उपचुनाव में काँग्रेस के अनिल शास्त्री के मुकाबले उतरे। वह चुनाव राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह काँग्रेस की सरकारी ताकत और संयुक्त विपक्ष (23 पार्टियां) की एकजुट ताकत का टकराव था। इसके परिणामों का 1989 में होने वाले आम चुनाव की राजनीति पर असर पड़ने वाला था। कांशी राम ने काँग्रेस और संयुक्त विपक्ष के इस संघर्ष में अपना स्वतंत्र दावा किया ताकि वे स्वयं की तीसरी धारा के रूप में शिनाख्त करा सके। यह आसान काम नहीं था। कांशी राम को सन्मानजनक वोट मिलने ही चाहिए थे तकी वे खुद को समान स्तर की राजनीतिक ताकत सिद्ध कर सकते थे। काफी कुछ दांव पर था। इसलिए कांशी राम ने किसी और को न लड़ा कर स्वयं को उम्मीदवार के रूप में पेश किया। इस चुनाव की पूर्वपीठिका के रूप में बहुजन समाज पार्टी साल भर से अपना सोशल एक्शन कार्यक्रम चला रही थी। 15 अगस्त 1987 से ही प्रदेश भर में छुआछुत, अमानवीयता, अन्याय, असुरक्षा और असमानता के खिलाफ बसपा के धरने और साइकिल यात्राएं जारी थी।¹¹

बसपा का सांगठनिक ढांचा और आंदोलन की विधि

इस चुनावी कामयाबी के पीछे कांशीराम का कठोर परिश्रम और अपने जनाधार के सतत सम्पर्क में रहने की खूबियां मुख्य थी। उन्होंने निरंतर प्रचार यात्राएं कीं और आंदोलनकारी कार्यक्रम किए। बहुजन समाज पार्टी

की संगठन शैली उन्होंने अपने आंदोलन की व्यावहारिक जरूरतों के आधार पर निर्धारित की, न कि पार्टी बनाने की किसी पूर्वस्थापित शैली के आधार पर। उनकी मान्यता थी कि जैसे-जैसे बहुजन समाज बनता जाता है वैसे-वैसे पार्टी भी बनती जाती है और जब जरूरत पड़ती है तो वे बसपा में एक पुर्जा और जोड़ देते हैं।¹³ अर्थात् काशी राम की बसपा सतत निर्माण की अवस्था में रहती है।

काशीराम ने संगठन की दृष्टि से बसपा का गठन करने हेतु पूरे देश को सौ डिवीजनों में बांटा। सारे देश में साढ़े तीन हजार से ज्यादा बसपा दफ्तर खोले गए। पार्टी का मुख्यालय दिल्ली में रहा और काशी राम उसके निर्विवाद प्रमुख बने। शुरू में कोई और पदाधिकारी था ही नहीं। न कोई मंत्री, न कोई महामंत्री। सभी पार्टी के कार्यकर्ता थे। तकनीकी रूप से अध्यक्ष सही, पर काशी राम स्वयं को भी कार्यकर्ता कहना पसंद करते थे। प्रांतीय और स्थानीय स्तर पर पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता को संयोजक कहा जाता था। इसे अक्सर अध्यक्ष के नाम से भी बुलाया जाता है। शुरू में प्रांतीय कार्यालय नहीं खोले गए थे—लेकिन बाद में उप्र जैसे राज्यों में और अन्य कुछ राज्यों में प्रांतीय कार्यालय स्थापित हुए। बसपा में अभी तक आंतरिक चुनाव होते नहीं देखे गए हैं। न ही उसका कोई घोषणा पत्र अथवा नीति वक्तव्य है। काशी राम के बयान, उनके द्वारा लिखित पर्चों, आंदोलनों के दौरान की गई घोषणाओं, विभिन्न राष्ट्रीय समस्याओं पर की गई उनकी टिप्पणियों से ही इन आवश्यकताओं की थोड़ी बहुत भरपाई हो पाती है। पूरी पार्टी पर काशी राम का कठोर नियंत्रण रहा है।

बसपा की एक रिसर्च शाखा भी है। काशी राम इसमें अपनी पसंद के बुद्धिजीवियों को रखते हैं। इसका सदस्य कुछ स्थायी और अस्थायी रहते हैं। जरूरत पड़ने पर इसकी उपकमेटियां भी बनाई जाती हैं। यह नीतिगत निर्णय लेने या अनुमोदन करने के अलावा जातीय इतिहास की खोज, मिथकों का निर्माण एवं इतिहास की व्याख्या और बीएसपी साहित्य का निर्माण करती है। इसी प्रकार मंडल या जिला स्तर पर भी रिसर्च विंग होते हैं जो राष्ट्रीय शाखा के अनुरूप ही कार्य करते हैं। इसमें सदस्यों की नियुक्तियां मंडलीय संयोजक द्वारा की जाती हैं। बसपा के पास अपना एक खुफिया विभाग भी है। यह सूचनाएं प्राप्त कर पार्टी अध्यक्ष के पास तक पहुंचाता है। सूचनाएं जमा करने की मुख्य भूमिका बामसेफ के सदस्य अदा करते हैं। स्वयं काशी राम कहते हैं कि 24 घंटे की भीतर अन्य पार्टियां या सरकार क्या करती हैं, हमें इसकी सूचना मिल जाती है।¹⁴ हमारे आदमी हर विभाग में हैं, जो हमें सूचनाएं देते रहते हैं। पार्टी के पास अपने सुरक्षा गार्ड हैं। पार्टी सम्मेलनों में इसी सुरक्षा गार्ड को तैनात किया जाता है। पुलिस विभाग की सहायता नहीं ली जाती। पुलिस यदि सुरक्षा की दृष्टि से सम्मेलन के परिसर के अंदर प्रवेश कर जाती है तो उससे पार्टी स्वयंसेवक अनुरोध करते हैं कि वह सम्मेलन क्षेत्र से बाहर चली जाए क्योंकि हम अपनी सुरक्षा खुद कर लेंगे। सुरक्षा गार्ड गारंटी देते हैं कि कोई किसी प्रकार से कानून-व्यवस्था भंग नहीं करेगा। पुलिस की सहायता न लेने की पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण है। पुलिस की सहायता न लेकर बसपा यह सिद्ध कर रही है कि उत्पीड़ित वर्ग में साहस है, और वह आत्मरक्षा कर सकता है।

सुरक्षा गार्ड की स्थापना के पीछे एक उद्देश्य सवर्णों की हिंसक कारवाइयों का उत्तर देना भी है। सुरक्षा गार्ड का सदस्य बनने की कोई निश्चित योग्यता नहीं है फिर भी शारीरिक रूप से पुष्ट तथा साहसपूर्ण व्यक्ति को, मंडल या जिला संयोजक इसमें नियुक्त करता है। जिला स्तर पर इस विंग का एक प्रमुख होता है, जिसकी नियुक्ति सीधे काशी राम द्वारा की जाती है। गार्डों को दिए गए निर्देशों में कहा जाता है कि आप लोग ईट का जवाब पत्थर से दें। सुरक्षा गार्ड नीले रंग की पेंट तथा सफेद शर्ट पहनते हैं। उनके हाथ में लाठी होती है। बंदूक किसी सुरक्षा गार्ड के पास नहीं होती। काशीराम के सम्मेलन क्षेत्र में आत-जाते समय सुरक्षा गार्ड मुख्य द्वार से मंच तक पंक्तिबद्ध ढंग से दोनों किनारों पर खड़े हो जाते हैं। काशी राम उनके बीच आते-जाते थे।

उच्च जाति के लोग नेतृत्व ग्रहण नहीं कर सकते

काशीराम कहते थे कि उच्च जाति के लोग पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन वे नेतृत्व ग्रहण नहीं कर सकते। नेतृत्व बहुजनों के हाथ में ही रहेगा, “उच्च जाति के लोग हमसे कहते हैं, कि हमको क्यों नहीं लेते। मैं कहता हूँ कि आप सभी पार्टियों में नेतृत्व कर रहे हैं। यदि आप हमारी पार्टी में सम्मिलित होते हैं, तो यहां आप परिवर्तन को रोक देंगे। उच्च जाति के लोगों को पार्टी में लेने में मुझे भय है। वे यथास्थितिवादी होते हैं तथा नेतृत्व ग्रहण करने की कोशिश में सदा रहते

हैं। इससे वे हमारे व्यवस्था परिवर्तन के प्रक्रिया को रोक देंगे। जब यह भय दूर हो जाएगा, तो उन्हें भी पार्टी में ले लूंगा।”

1994 के आसपास बीएसपी में एक लाख से अधिक कार्यकर्ता थे। कांशी राम ने अपना लक्ष्य एक घर से एक कार्यकर्ता बनाया है। कार्यकर्ता दो तरह के होते हैं—(1) पूरे समय के कार्यकर्ता तथा (2) कम समय के कार्यकर्ता। पूरे समय के कार्यकर्ता मिशन के कामों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं। इनका चुनाव व बड़ी सावधानी पूर्वक किया जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उनके ऊपर उनके परिवार को आश्रित नहीं होना चाहिए, वे किसी जिम्मेदारी से दबे हुए नहीं होने चाहिए तथा वे सामाजिक दायित्व से भी मुक्त होने चाहिए या मुक्त होने में सक्षम होने चाहिए। कम समय के कार्यकर्ता अवसर विशेष पर (चुनाव, इत्यादि) अपना पूरा समय पार्टी के कार्यों में लगाते हैं। इनका चुनाव स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है। कार्यकर्ता सफेद शर्ट और नीली पैंट पहनते हैं। पार्टी का झंडा नीला (आसमानी रंग) प्रतीक चिन्ह हाथी और परस्पर अभिवादन ‘जय भीम’ है।

बी.एस.पी. की क्या पहचान निला झंडा हाथी निशान

आसमानी रंग का झंडा रखे जाने का कारण आसमान जैसी ऊंचाई और निर्मलपन का प्रतीक होना और समूह का द्योतक होता है। हाथी भीमकाय जानवर है और अपनी मस्ती में आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। उस पर अपने प्रतिपक्षी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी मान्यता के परिणाम स्वरूप ‘हाथी’ बीएसपी का प्रतीक चुनाव चिन्ह है। समर्थक तथा कार्यकर्ता आपस में ‘जय भीम’ कहकर एक दूसरे को नमस्कार करते हैं। यह ब्राम्हणवाद से अलगाव और आंबेडकरवाद से लगाव का प्रतीक माना जाता है।¹⁵

राष्ट्रव्यापी साइकिल यात्रायें

15 अगस्त 1988 से 15 अगस्त 1989 के बीच कांशी राम ने पांच सूत्रीय सामाजिक रूपांतरण आंदोलन चलाया। ये पांच सूत्र थे— आत्मसम्मान के लिए संघर्ष, मुक्ति के लिए संघर्ष, समता के लिए संघर्ष, जाति उन्मूलन के लिए संघर्ष और विभाजित समाज को भाई चारे से जोड़ने के लिए संघर्ष एवं 85 फीसदी भारतीय जनता के ऊपर अस्पृश्यता, अन्याय, अत्याचार और आतंक थोपने के खिलाफ संघर्ष। कांशी राम ने इसके लिए साइकिल यात्राओं की अनूठी विधि निकाली और देश के पांच क्षेत्रों से पांच साइकिल यात्राएं निकालीं। 17 सितंबर 1988 को कन्याकुमारी से ईवी रामस्वामी नाइकर पेरियार के जन्म दिन पर पहिली यात्रा शुरू हुई। दुसरी यात्रा कोहिमा से चली। तिसरी कारगिल से चली। चौथी पुरी से और पाचवी पोरबंदर से चली। ये सभी यात्राएं 27 मार्च 1989 को दिल्ली पहुंचकर आपस में जुड़ गईं। कांशी राम ने 1989 में पूरे देश में घूम-घूम कर छह सम्मेलन किए। 10 सितंबर को मुरादाबाद में पहला सम्मेलन हुआ जिसके केंद्र में मुसलमान

काँग्रेस और विपक्ष में नजदीकी संघर्ष जरूरी

इस बीच बसपा ने उत्तर प्रदेश में म्युनिसिपल और ग्राम पंचायत चुनावों में भी हिस्सा लिया और अच्छी सफलता प्राप्त की।¹⁶ 1989 के लोकसभा और विधान सभा चुनावों में बसपा ने स्वतंत्र रूप से उम्मीदवार लड़ाए और तीन सांसदों और 15 विधायकों को उप्र और मप्र से जिताने में सफलता प्राप्त की। कांशीराम ने दावा किया कि उनके उम्मीदवारों ने 31 निर्वाचन क्षेत्रों में नंबर दो पर रहने का श्रेय प्राप्त किया है इसलिए उसकी जीती हुई तीन सीटों के आधार पर ही उनकी ताकत का आकलन नहीं किया जाना चाहिए।¹⁷ इस चुनाव में कांशीराम ने एक और दिलचस्प प्रयोग किया। वे अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से

राजीव गांधी के खिलाफ खड़े हो गए। विपक्ष ने राजीव का मुकाबला करने के लिए महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी को उतारा। एक बड़े समाचार पत्र समूह के मालिक राजमोहन गांधी के चुनाव अभियान को चलाने में विशेष योगदान किया। इलाहाबाद उपचुनाव के बाद यह दूसरा मौका था जब काशी राम अपनी विशिष्ट ताकत को राष्ट्रीय राजनीतिक मंच पर पेश कर सकते थे। विपक्ष ने इस चुनाव में बहुत जोर बांधा और समाचार माध्यमों ने जो छवि पेश की, उससे लगा कि राजीव गांधी के हारने की संभावना भी है।

“मैंने अपना पक्ष उभारने के लिए राजीव के खिलाफ चुनाव लड़ा लेकिन मैं उन्हें चुनाव हाराना नहीं चाहता था। क्योंकि उससे तो विपक्ष को बहुत ज्यादा फायदा हो जाता।”¹⁸ इलाहाबाद और अमेठी के चुनावों में काशीराम की भूमिका के बारे में कहा जा सकता है कि भारतीय राजनीति के उस संक्रमणकाल में उन्होंने पहले कांग्रेस को हरवाने में और फिर विपक्ष की बढ़त रोकने में भूमिका निभाई। इलाहाबाद से वीपी सिंह की जीत भी प्रतीकात्मक थी और अमेठी में राजमोहन गांधी की उम्मीदवारी भी। संसदीय राजनीति के इन दो प्रतीक संघर्षों को चुन कर काशी राम ने बहुजन समाज को संदेश दिया कि वे भविष्य में किस तरह की राजनीति करने जा रहे हैं। यह शक्ति संतुलन की राजनीति की आहट थी तो यह बताती थी कि उत्पीड़ित वर्ग का वोट अब पहले की तरह इस या उस पक्ष में नहीं पड़ता वरन भविष्य की समझी-बूझी आयोजना के मुताबिक सवर्ण वर्ग की पार्टियों के आपसी संतुलन से भी खेलता है।

पचास हजार कि.मी. समाज परिवर्तन प्रचार यात्रा का नेतृत्व

1990 में काशीराम ने डॉ. भीमराव आंबेडकर की जन्म शताब्दी मनाने के लिए 130 दिन लंबी प्रचार यात्रा आयोजित करने का निश्चय किया। यह यात्रा 13 प्रमुख राज्यों से संपर्क करते हुये आगे बढ़ी। इसमें काशी राम जहां-जहां गए, बहुजन और अतिपिछड़ों की भीड़ उनके चारों ओर उमड़ पड़ी। 6 दिसंबर 1990 को आंबेडकर की पुण्य तिथि के अवसर पर काशीराम ‘सामाजिक रूपांतरण वाहन’ में सवार हुए। स्थान था भारत का दक्षिण सिरा कन्याकुमारी। इस वाहन में एक स्वागत कक्ष, एक शयन कक्ष, एक शौचालय और एक स्नान घर था। इसमें एक जनरेटर, प्रकाश प्रणाली और माइक्रोफोन सिस्टम भी फिट था। तामिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर व चंडीगढ़ होते हुए यह प्रचार यात्रा आंबेडकर के जन्म स्थान पर पहुंची। काशी राम ने 130 दिन लंबे इस दौरे का निर्देशन स्वयं किया। 15 मार्च 1991 को जब यह प्रचार यात्रा नई दिल्ली के वोट क्लब मैदान पर पहुंची तो उसके स्वागत में जबर्दस्त रैली हुई।¹⁹

प्रचार यात्रा जब पंजाब पहुंची तो काशी राम मुद्दतों बाद अपने गांव और परिजनों से मिलने गए। मां और बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। उन्हें अमृतसर के स्वर्ण मंदिर और आनंदपूर साहिब गुरुद्वारे में पूरा सम्मान दिया गया। 230 दिन में 50 हजार किमी की यात्रा करके प्रति दिन 20 जनसभाएं करते हुए काशी राम 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के मऊ में पहुंचे जहां सौ साल पहले आंबेडकर का जन्म हुआ था। काशीराम ने मऊ में एक प्रचण्ड रैली की। बहुजन समाज रैली में उमड़ पड़ा। यह एक बहुत बड़ी कामयाबी थी।

संदर्भ –

1. एसएस अब्राहम, एंड जस्टीफाइस द मीसे, टाइम्स आफ इंडिया, दिल्ली 8 अगस्त 1996.
2. ए. आर. अकेला, काशीराम प्रेस के आईने में आनन्द साहित्य सदन, अलीगढ़, 2001
3. ए. आर. अकेला, उपरोक्त पृ. 11
4. संडे, 11 दिसंबर 1988.
5. आम्बेथ राजन, माई बहुजन समाज पार्टी, एबीसीडोई प्रकाशन, दिल्ली, 1996, पृष्ठ 8.
6. उपरोक्त पृ. 11
7. ए. आर. अकेला, उपरोक्त पृ. 16
8. द वीक, 16 अप्रैल 1992.
9. सूर्या इंडिया, अप्रैल 1992.
10. आम्बेथ राजन, उपरोक्त, पृष्ठ 9.

11. आम्बेथ राजन, उपरोक्त, पृष्ठ 9.
12. आम्बेथ राजन, उपरोक्त,
13. आर. के. सिंह, उपरोक्त, पृ. 92
14. ए. आर. अकेला, उपरोक्त पृ. 31
15. आम्बेथ राजन, उपरोक्त,
16. आम्बेथ राजन, उपरोक्त
17. पेट्रियट, चार मई, 1996.
18. द ऑफ़ेन्सिव इंडियन, अप्रैल 1979
19. आम्बेथ राजन, उपरोक्त ।